

उत्तराखण्ड में कृषि का विविधिकरण एक आर्थिक सूक्ष्म विश्लेषण

डॉ० महेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
एस0जी0आर0आर0 पीजी कालिज, देहरादून
ईमेल: mkrajoor@gmail.com / drkumar1580@gmail.com

सारांश

कृषि विविधिकरण आर्थिक विकास के आवश्यक घटकों में से एक है। यह वह चरण है जहां पारंपरिक कृषि उत्पाद मिश्रण को उच्च मानक उत्पादों में स्थानांतरित करके पारंपरिक कृषि को एक गतिशील और वाणिज्यिक क्षेत्र में बदल दिया जाता है, जिसमें उत्पादन दर को उत्तेजित करने की उच्च क्षमता होती है। उत्तराखण्ड हिमालय एक पारंपरिक कृषि समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जहां 74 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपनी जीविका चलाने के लिए अनाज, फसलों की खेती पर निर्भर करती है। समय के साथ-साथ, मानव जनसंख्या में वृद्धि और प्रति व्यक्ति भूमि में कमी के साथ, पारंपरिक निर्वाह कृषि खाद्य आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका है।

हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र साधारणतः अर्द्ध विकसित है। इस क्षेत्र के आर्थिक कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुछ प्रगति हुई है इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता परन्तु हिमालय क्षेत्र में परिस्थितियों की निम्न दशा का मुख्य कारण निर्धनता और बेरोजगारी है। यदि हिमालय क्षेत्र में परिस्थितिकी के अनुभव से देखा जाये तो यह मैदानों से जुड़े एक बड़े क्षेत्र और चक्रीय पर्यावरण के लिये गम्भीर प्रतिघात है। क्षेत्र की विषम रथलाकषणि, विरल जनसंख्या अधिकतम पहुँच से बाहर दूर-दूर तक फैले हुये छोटे-छोटे गांव, पथरीली भूमि और वर्षा से सिंचित सीमित क्षेत्र, कृषिकृत अर्थव्यवस्था पुरुषों का परदेश में बसना, महिलाओं का कृषि के प्रति जिम्मेदार होना आधुनिक उन्नति आदानों के साथ न्यून सिंचाई निम्न उत्पादकता को बरकरार रखते हैं। यातायात व संचार साधनों की कमी, उचित मार्केटिंग का क्रेडिट संगठन का अभाव आदि की अपनी विशेष समस्यायें हैं। तदनुसार क्षेत्र और लोग तकनीकी रूप से पिछड़े और गरीब होते जा रहे हैं। राज्य में साधारणतः सिंचाई, सड़कें, बाजार, औद्योगिक वातावरण, संस्थात्मक विनत आदि अधः संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है।

प्रस्तावना

हाल के वर्षों में कृषि का विविधीकरण एक रणनीति के रूप में नवीन वर्षों से देश में बनी योजनाओं को ध्यान में रखते हुये महत्वपूर्ण विकसित लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। यह रणनीति आर्थिक पर्यावरण में बदलाव के कारण कृषि क्षेत्र के उत्पादन कार्यों को बदलने और बढ़ती

5. Joshi, P.K., Gulati A., Birthal P. S., and Tiwari L. 2004: *Agriculture Diversification in South Asia: Pattern, Determinants and Policy Implications*. Economic and Political Weekly, June 12.
8. Arora APS, Srivastava SK. : *Diversification of Cropping Pattern and Food Grain Mix in India - Pace, Magnitude and Implications*. Indian Journal of Agricultural Economics. 1996.
9. Bhalla GS, Singh G. *Growth of Indian agriculture: a district level study*. Planning Commission.GOI, 2010.
10. Chand KP, Singh R. *Diversification of agriculture in Himachal Pradesh: A Spatio temporal analysis*. Indian Journal of Agricultural Economics. 1985.
11. Joshi PK. *Crop Diversification in India: Nature, Pattern and Drivers*. National Centre for Agricultural Economics and Policy Research.New Delhi; 2005.
12. Mehta PK. *Diversification and Horticultural Crops: A Case of Himachal Pradesh*. Diss. Department of Economics, University of Mysore. 2009.
13. Shah SL. *Farming systems in hill areas*.Indian Journal of Agricultural Economics. 1979.
14. Sharma BR, Chand R. *Diversification of agriculture: an aid to employment generation in rural area*. Agricultural Situation in India. 1992.
15. *ESTIMATES OF STATE DOMESTIC PRODUCT OF UTTARAKHAND*, Directorate of Economics & Statistics of Uttarakhand Dehradun.
16. *UTTARAKHAND AT A GLANCE*, Directorate of Economics & Statistics of Uttarakhand Dehradun.
17. सांख्यिकी डायरी उत्तराखण्ड (विभिन्न अंक) अर्थ एवं सांख्या निदेशालय नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
18. कुरुक्षेत्र : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
19. योजना : सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
20. उत्तराखण्ड में उद्योगों का विकास प्रगति समीक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।